School of Humanities
U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

Certificate

I hereby declare that the short synopsis **"पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण विकास में ई- गवर्नेंस (जी टू सी) सेवाओं की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"** being submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in **Journalism and Mass Communication** under the **School of Humanities**, U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj during the academic year **2024** .It is a bona fide record of original work carried out under the supervision of **Dr. Sadhana Srivastav** and has not been submitted in full or part to any other university or institute for a degree or diploma. Further, it is certified that the short synopsis is plagiarism-free and the report has been submitted.

अभय शुक्ला

(Abhay Shukla)
(Enrol. No.:**2200401**)
16/05/2025

Research Supervisor & Co-Supervisor (If any)

Sadhana

(Dr. Sadhana Srivastav)
Faculty of Journalism and Mass Communication

डॉ. साधना श्रीवास्तव
सहायक आचार्य
पत्रकारिता एवं जनसंचार, मानविकी विद्याशाखा
उ०प्र०रा०ट०मु०वि०वि०, प्रयागराज

16/05/025
(Prof. Satyapal Tiwari)
(Director, School of Humanities)

16/05/25
(Prof. P. K. Pandey)
(Director, R&D Cell)

पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण विकास में ई- गवर्नेंस (जी टू सी) सेवाओं की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

SHORT SYNOPSIS

Submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY

in
Journalism and Mass Communication
to
U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

अभय शुक्ला
16/05/2025

by
Abhay Shukla
Enroll. No. 2200401

Under the Supervision of
Sadhna
Dr. Sadhana Srivastava
Faculty of Journalism and Mass Communication

डॉ0 साधना श्रीवास्तव
सह आचार्य
पत्रकारिता एवं जनसंचार, मानविकी विद्याशाखा
उ0प्र0रा0ट0मु0वि0वि0, प्रयागराज

School of Humanities
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Shantipuram (Sector –F), Phaphamau, Prayagraj –211013

ABSTRACT (सार):

यह शोध कार्य "पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस (जी टू सी) सेवाओं की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है ई-गवर्नेंस शासन और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में नागरिकों और सरकार के मध्य सतत पारस्परिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। जो नागरिकों को सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न सेवाओं तक सीधा पहुँच बनाने में सक्षम करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों तक ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच, उनके उपयोग के स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के चयनित जिलों (गोरखपुर ,वाराणसी और प्रयागराज) के ग्रामीण नागरिकों को केंद्र में रखते हुए मनरेगा, ई-डिस्ट्रिक्ट, जनसुनवाई समाधान, डिजिटल इंडिया और अन्य प्रमुख जी2सी सेवाओं का गहन मूल्यांकन किया गया है। शोध में मिश्रित शोध पद्धति अपनाई गई है जिसमें 666 नागरिकों और 90 जन सेवा प्रदाताओ से प्रश्नावली, जन सेवा प्रदाताओ और सक्षम प्रसासनिक अधिकारियों से साक्षात्कार और ग्रामीण नागरिकों का अवलोकन करते हुए आंकड़े संकलित किए गए हैं। अध्ययन में यह पाया गए परिणामों से यह जानने में सहायक होगा की कैसे ई-गवर्नेंस सेवाएँ ग्रामीण नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं, विशेषकर सेवा वितरण की पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और एक प्रभावी संचार माध्यम के रूप में। हालाँकि, डिजिटल साक्षरता की कमी, आधारभूत संरचना की सीमाएँ और जागरूकता की कमी जैसी बाधाएँ सेवाओं के प्रभाव को सीमित कर रही होंगी, पर शोध निष्कर्षों के आधार पर नीति-निर्माताओं को ठोस रणनीतियाँ सुझाई जाएगी, ताकि ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके और सतत ग्रामीण विकास को सशक्त बनाया जा सके। यह अध्ययन विकास संचार के अंतर्गत शासन और प्रौद्योगिकी के अभिसरण से प्रभावी और भागीदारिपूर्ण संचार पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण विकास, ई-गवर्नेंस, जी2सी सेवाएँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), नागरिक भागीदारी, सतत विकास, विकास संचार

Sadhna अक्षय शुक्ला

CONTENTS

Sr. No.	Description	Page No.
1	Introduction	5-10
2	Literature Review	10-13
3	Description of the Broad Area	13-14
4	Objectives of the Study	14-14
5	Research Methodology	14-17
6	Expected Outcome of the Research	17-18
	References	
	Plagiarism Report	

1.0 प्रस्तावना

भारत के उत्तर मध्य में स्थित भूभाग को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत अधिकांश जिले उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आते हैं पूर्वांचल की भौगोलिक सीमाएं पूर्व दिशा में बिहार, पश्चिम दिशा में अवध क्षेत्र, उत्तर दिशा में नेपाल की सीमा और दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा से मिला हुआ है। इसके अधिकतर क्षेत्र तराइन और गंगा के निचले मैदानी भागों में आता है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है जो अपनी विशिष्ट भाषाई, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वैसे तो कल 19 जिले आते हैं परंतु इनमें से प्रमुखता में वाराणसी, गोरखपुर और इलाहाबाद (प्रयागराज) जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। "यह क्षेत्र लगभग 51,125 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें उपजाऊ मैदान, गंगा और घाघरा जैसी नदियाँ और वन क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की आबादी 7.653 करोड़ से अधिक है जिसमें से अधिकांश मुख्य रूप से ग्रामीण है जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है"। यह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है जिसमें भोजपुरी और अवधी भाषाओं की मजबूत उपस्थिति है पर इस क्षेत्र को भोजपुर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। होली, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख शहरों में वाराणसी और प्रयागराज हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है जो अपने घाटों, मंदिरों और संस्कृत समृद्धता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पूर्वांचल की अर्थव्यवस्थां की प्रमुख स्रोत कृषि है जिसमें गाना गेहूं और धन प्रमुख फसलों में आती हैं। इस क्षेत्र में चीनी मिलों के साथ के साथ कपड़ा निर्माण और कुटिल उद्योग का एक बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। अपनी घनत्व आबादी और अन्य कारणों से इस आर्थिक क्षमता के होने के बावजूद पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में उच्च गरीबी दर जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। शैक्षणिक स्तर पर पूर्वांचल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इसी के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय (नाक का A++ ग्रेट) के साथ अन्य कई विश्वविद्यालय स्थापित है।

1.1 ग्रामीण क्षेत्र

भारत में ग्रामीण क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है जहा कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था और जीवनशैली होती है वही बुनियादी सुविधाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में सीमित होता है। भारत की जनगणना के अनुसार, "एक क्षेत्र को ग्रामीण माना जाता है यदि:

1. वहाँ की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोगों से कम हो।
2. क्षेत्र के कार्यबल का कम से कम 75% कृषि या संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो।
3. वहाँ पर नगर निकाय या निगम जैसी शहरी स्थानीय प्रशासनिक इकाई न हो"।

ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान उसकी पारंपरिक जीवनशैली, मजबूत सामुदायिक बंधनों, लोगों का कृषि और हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों पर निर्भरता से होती है। इन क्षेत्रों में अवसंरचना अक्सर अविकसित या अर्धविकसित होती है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं की सीमित पहुँच होती है। यहां मौसमी बेरोजगारी, बाजारों और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ हैं। फिर भी, ये क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का केंद्र हैं जो देश के सामाजिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

1.2 ग्रामीण विकास

भारत की पहचान गांव के देश के रूप में दुनिया भर में होती है। भारत में अभी भी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार "ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में करीबन आधी भागीदारी रखती है और रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 5 वर्ष में 10 फीसदी बढ़ोतरी की है"। यदि ग्रामीण विकास का उल्लेख करें तो ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसानों और ग्रामीण समुदायों की जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कई प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का संगठन करती है। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि साथ ही ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। ग्रामीण विकास विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कई योजनाएं को शामिल करता है जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की को प्राथमिकता देना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण

Sadhna

अभय श्रीवास्तव

आवास योजना, मनरेगा, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देना है। ग्रामीण विकास के कई पहलू होते हैं, जैसे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, और सामाजिक सुरक्षा। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास का मुख्य ध्यान होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक आधार कृषि पर ही टिका होता है। किसानों के लिए नई तकनीकों और कृषि योजनाओं का प्रयोग करने के लिए संचालन किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए स्कूल और कलेजों की स्थापना की जाती है ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बढ़ाई जाती है ताकि ग्रामीण समुदायों के लोग स्वस्थ रह सकें। औद्योगिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने और उन्हें विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं और समर्थन प्रदान किए जाते हैं। इससे रोजगार की स्थिति में सुधार होता है और लोग अधिक आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा भी ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं शामिल होते हैं जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिलाएं ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई समृद्धि योजनाओं का हिस्सा बनती हैं।

1.2.(1) ग्रामीण विकास के तत्व

कृषि और पशुपालन - ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि और खेती का होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और पशुपालन के लिए तकनीकी समर्थन को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है।

लघु एवं कुटीर उद्योग - बुनाई, वस्त्र निर्माण, और हस्तशिल्प जैसे लोक कला और उद्योग ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

बुनियादी ढांचा - किसी भी विकास कार्य के लिए प्राथमिक स्तर बुनियादी ढांचे की संरचना होती है जो प्रत्येक चरण में विकास कार्यों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है।

शिक्षा - ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे लोगों के ज्ञान और कौशल में सुधार हो सके।

स्वास्थ्य सेवाएँ - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और परिस्थितियों को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है।

रोजगार अवसर - नौकरियों के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक हैं, ताकि लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

पर्यावरण सुरक्षा - पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सके।

सामाजिक संरचना - समुदाय की सामाजिक संरचना, जैसे कि सशक्तीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, और सामुदायिक सहयोग, ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

1.3 गवर्नेंस

गवर्नेंस जिसका मतलब प्रबंधन होता है वह ढांचा, प्रक्रिया और प्रणाली है जिससे एक संगठन या समाज निर्णय लेता है और नियंत्रण किया जाता है। इसमें वे तंत्र, संस्थाएँ और प्रथाएँ शामिल होती हैं जो जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, स्थिरता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करती हैं (OECD, 2015)। गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नीतियों की स्थापना और उनके क्रियान्वयन की सतत निगरानी करना है। इसमें औपचारिक तंत्र (जैसे कानून और नियम) और अनौपचारिक मानदंड एवं प्रथाएँ शामिल होती हैं। प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों की आवाज़ सुनी जाए और निर्णय लेने की शक्ति का दुरुपयोग न हो।

गवर्नेंस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन अक्सर पारदर्शिता, सहभागिता, और जवाबदेही जैसे मानदंडों के माध्यम से किया जाता है (World Bank, 2019)। इसमें विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि शक्ति का उपयोग निष्पक्ष और जिम्मेदारी से किया जाए (UNDP, 1997)।

1.4 ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस, या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं और नागरिकों और व्यवसायों के साथ सरकार की प्रबंधन

Sadhan

अभय शुक्ला

में डिजिटल प्रौद्योगिकी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का उपयोग करने को कहता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकारी प्रशासन की कुशलता, पारदर्शिता, पहुँच और प्रति क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है, साथ ही नागरिकों और व्यवसायों के साथ सरकारी अनुभवों को बढ़ावा देना है। ई-गवर्नेंस विभिन्न घटकों को शामिल करती है।

1. **ऑनलाइन सेवाएं**
2. **डिजिटल पहचान**
3. **ओपन डेटा**
4. **ई-भागीदरी**
5. **पारदर्शिता**

ई-गवर्नेंस के कई फायदे हैं। यह पेपरवर्क और मैन्युअल प्रक्रियाओं को कम करके सरकार की कुशलता को बढ़ाता है। नागरिक अपनी सुविधा को किसी भी स्थान से सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास कम होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही ओपन डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से बढ़ जाती है। इसके अलावा, ई-भागीदारी नागरिक संलग्न करती है, जिससे सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रति क्रियाशील होती है।
ई-गवर्नेंस डिजिटल प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर सरकारी प्रशासन के संचालन को आधुनिकीकरण करने, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आधुनिक समाजों के आगे बढ़ने के लिए इसके निरंतर विकास और कार्यान्वयन की जरूरत है।
भारत में ई-गवर्नेंस की चर्चा तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के 11 अध्याय में किया गया है उसके अनुसार ई-गवर्नेंस के अंतर्गत चार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है ।
सरकार-से-नागरिक (जी2सी): यह उन सरकारी सेवाओं को संदर्भित करता है जिनका उपयोग नागरिक करते हैं, जैसे कर भुगतान, पासपोर्ट आवेदन इत्यादि।
सरकार-से-व्यवसाय (जी2बी): इसका तात्पर्य सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच सेवाओं के आदान-प्रदान से है, जैसे लाइसेंसिंग, खरीद आदि।
सरकार-से-सरकार (G2G): यह विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं के बीच बातचीत को संदर्भित करता है, जैसे डेटा साझाकरण, नीति समन्वय, आदि।
सरकार-से-कर्मचारी (जी2ई): यह उन सेवाओं और सूचनाओं को संदर्भित करता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को प्रदान करती है, जैसे पेरोल, प्रशिक्षण, आदि।
इस शोध कार्य के अंतर्गत हम ई-गवर्नेंस के सरकार-से-नागरिक जी2सी पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहेगा।

1.5 सरकार से नागरिक (G2C)

सरकार से नागरिक (G2C) सेवाएँ ई-गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सीधे सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाकर सरकार और जनता के बीच बातचीत को सरल बनाना है ताकि पहुँच, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पारंपरिक शासन तंत्र अक्सर आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, G2C सेवाएँ सेवा वितरण में अंतराल को दूर करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में बहुत बड़ी संभावनाएँ रखती हैं।
पूर्वांचल क्षेत्र, जो गरीबी, निरक्षरता और सीमित बुनियादी ढाँचे जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की विशेषता रखता है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में G2C सेवाओं की भूमिका की जाँच करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन सेवाओं जैसी डिजिटल पहलों में शासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। हालाँकि, इन सेवाओं का सफल कार्यान्वयन और अपनाना डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढाँचे के विकास और स्थानीय शासन निकायों की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है।

अभय शुक्ला

Sadhna

यह शोध पूर्वांचल क्षेत्र की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने में G2C सेवाओं की प्रभावशीलता पर गहनता से विचार करता है। सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करके, अध्ययन का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाने, नौकरशाही की अक्षमताओं को कम करने और ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में इन सेवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करना है। इसके अलावा, यह उन बाधाओं की पहचान करना चाहता है जो G2C लाभों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालती हैं और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों का प्रस्ताव करती हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, यह अध्ययन ई-गवर्नेंस और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है, जो प्रौद्योगिकी और शासन के महत्वपूर्ण प्रतिच्छेदन को उजागर करता है। पूर्वांचल के अनूठे संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करके, इसका उद्देश्य ऐसी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करना है जो नीतिगत निर्णयों को सूचित कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए G2C सेवा वितरण को अनुकूलित कर सकें।

1.6 सूचना

सूचना वह डेटा है जिसका विश्लेषण किया गया हो, जरूरत के हिसाब से व्यवस्थित किया गया हो, या संरचित होकर ऐसा हो कि वह किसी मत या ज्ञान का संदेश पहुंचाता है। यह पाठ, संख्याएँ, छवियाँ, या किसी अन्य रूप में हो सकती है। जानकारी का उपयोग संवाद, निर्णय निर्माण, और हमारे आस-पास की दुनिया को समझने के लिए होता है। आमतौर पर यह तथ्य, विचार, निर्देश या दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होती है

शैनन-वीवर जिन्हें जानकारी सिद्धांत के पिता के रूप में माना जाता है उन्होंने अपनी पुस्तक A Mathematical Theory of Communication में सूचना की परिभाषा करते हुए कहा **"जो अनिश्चितता को कम करता है"** वह जानकारी है।

1.6.(1) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) आई.सी.टी. एक व्यापक और गतिशील क्षेत्र है जो जानकारी को प्रबंधित और आदान-प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को समाहित करता है। इसमें दूरसंचार, कंप्यूटिंग, और मीडिया का मेल होना शामिल है, जिससे संचार और डेटा प्रसंस्करण के नवाचारी तरीके बनते हैं। आई.सी.टी. ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, चाहे वह हमारे योग्यता के तरीके से हो, व्यापार के काम करने के तरीके से हो, या सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान करने के तरीके से हो। 2000 के प्रारंभ में आई.सी.टी. ने एक परिवर्तक परिवर्तन का सामना किया जिसने हमारे जीवन, काम और संवाद करने के तरीके को आकार दिया। Mobile, computer जैसे डिवाइस्स अधिक सस्ते और पहुँचने वाले बन गए, जो डिजिटल साक्षरता और उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद किया। साथ ही इंटरनेट का विस्तार हुआ, उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने संवाद और सूचना साझा करने को समर्थ बनाया। **टिम बर्नर्स-ली** का वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल जिसे 1980 के दशक में विकसित किया गया था, जिसने लोगों को वैश्विक रूप से सूचना तक पहुँचने और साझा करने का तरीका पूर्ण किया।

आई.सी.टी. का समाज पर गहरा असर है, और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और शासन के विभिन्न पहलुओं पर दूर तक पहुँच चुका है। उदाहरण के लिए, यह शिक्षा को E-Learning प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कैसे क्रांति कर दी है, जिससे ज्ञान को वैश्विक रूप से पहुँचाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य देखभाल में, टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ने रोगी देखभाल को सुधारा है। व्यापार में, आई.सी.टी. टूल्स जैसे कि ग्राहक संबंध प्रबंधन (CMS) सिस्टम कार्यवाहन को संघटित करते हैं, और ई-व्यापार प्लेटफॉर्म वैश्विक व्यापार को संभावित करते हैं। इसके अलावा, आई.सी.टी. सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करके नागरिकों को जानकारी तक पहुँचने, जानकारी को प्रयोग में लेना और प्रयोग में ली गई जानकारी को जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन भी आई.सी.टी. के महत्व को मानता है, जैसा कि आई.सी.टी. इसका प्रमाण Sustainable Development Goal 9 में दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत विकास और नवाचार के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।

अभय शुक्ला

Sadhan

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दो शब्दों के मिलन से निर्मित है जिसमें सूचना अर्थात संदेश और संचार अर्थात संदेश को पहुंचाने का माध्यम है ।

1.6.(2) संचार

संचार मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे सामाजिक, व्यक्तिगत, और व्यापारिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी, विचार, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने सकते है। संचार का उद्देश्य समझने और समझाने में मदद करना, ज्ञान और जानकारी का आदान-प्रदान करना, और रिश्तों को मजबूत बनाना है और यह सोशल और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि भाषा, लेखन, श्रवण, और दृश्य कला। हम मौखिक संचार के माध्यम से बात करके और लिखित संचार के माध्यम से पत्र, लेख, और संदेश भेजकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते है। इसके अलावा, श्रवण संचार के द्वारा हम दूसरों के बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर समझते हैं, और दृश्य कला के माध्यम से हम चित्रों, चित्रकला, और फोटोग्राफी के जरिए जानकारी प्राप्त करते हैं। संचार का मुख्य उद्देश्य जानकारी को सही और स्पष्ट तरीके से प्रसारित करना होता है।

"**शैनन और वीवर (1949)** क्लोड शैनन और वॉरेन वीवर, दो गणितज्ञ और इंजीनियर, ने संचार को जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया"।

"**बर्लो (1960)** डेविड के. बर्लो ने संचार को विचार, जानकारी, और संदेशों को दूसरों के साथ साझा करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने जोर दिया कि प्रभावकारी संचार में संदेश को एनकोड करने और डिकोड करने, संदर्भ को ध्यान में रखने, और प्रतिक्रिया को समझने की आवश्यकता है"।

"**म्कलूहैन (1964)** मार्शल म्कलूहैन, एक मीडिया सिद्धांतकार ने मशहूर कहा है, "मीडियम संदेश है" उन्होंने कहा कि संचार बस संदेश की सामग्री के बारे में ही नहीं है, बल्कि उस माध्यम या चैनल के बारे में भी है जिसके माध्यम से यह प्रेषित किया जाता है"।

1.6.(2.1) विकास संचार

विकास संचार कई सैद्धांतिक रूपरेखाओं पर आधारित है जो इसके सिद्धांत का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा ही एक सिद्धांत काट्ज़ और लेज़र्सफेल्ड (1955) द्वारा प्रस्तावित टू-स्टेप फ़्लो थ्योरी है जो बताता है कि मीडिया संदेश पहले जनमत नेताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो फिर व्यापक जनता तक जानकारी प्रसारित करते हैं। यह मॉडल जनता की राय और व्यवहार को प्रभावित करने में पारस्परिक संचार के महत्व को दर्शाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार रोजर्स (1962) द्वारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है जो उस प्रक्रिया की जांच करता है जिसके माध्यम से नए विचार, प्रौद्योगिकियां और प्रथाएं एक समाज के भीतर फैलती हैं। विकास संचार इस सिद्धांत का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में नवाचारों को कैसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित करके अपनाया जा सकता है।

विकास संचार एक बहु-विषयक संगठित स्वरूप है जिसमें सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना, विचारों और ज्ञान का आदान-प्रदान शामिल है। यह समुदायों के भीतर भागीदारी प्रक्रियाओं, सहयोग और सशक्तीकरण को बढ़ावा देकर सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस व्यापक दृष्टिकोण में विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए संचार रणनीतियों और उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल है।

विकास संचार के घटक:

1. आधुनिकरण दृष्टिकोण - यह दृष्टिकोण.पूंजीवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और यह मानता है कि रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित जन संचार माध्यम सूचना प्रसारित करने और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत (काट्ज़ एट अल., 1974) बताता है कि कैसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से मीडिया का चयन और उपयोग करते हैं। विकास संचार इस सिद्धांत का उपयोग मीडिया संदेशों द्वारा आधुनिकरण और पश्चिम विचारों के समर्थन के लिए किया जाता है।।

2. सहभागी दृष्टिकोण: विकास संचार निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने पर जोर देता

अक्षय शुक्ला

Sadhan

है। पाउलो फ्रेयर द्वारा 1970 में पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन मॉडल का विकास किया गया था जिसमें विकास गतिविधियों को सतत रूप देने के लिए आम सहमति तक पहुंचने के तरीके के रूप में संवाद और दो-तरफा संचार पर जोर देता है। जिसका अर्थ है विकास अभ्यासकर्ता और समुदायों के बीच संवाद, सहयोग और साझा निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।

3. बहुलतावादी दृष्टिकोण - जान सर्वेस (1986) ने विकास संचार का "बहुलता" प्रतिमान पेश किया। जिस प्रतिमान के अंतर्गत बताया गया कि विकास एक बहुआयामी और विचारों के संवाद की प्रक्रिया है जिसका कोई एक सर्व भौतिक मार्ग नहीं हो सकता है यह अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में भिन्न हो सकती है।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

इस अध्ययन कार्य के अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लिया गया है

- नवाचार के प्रसार का सिद्धांत **(ई. एम रोजर्स)**
- उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत **(काट्ज और ब्लमलर)**
- विकासात्मक संचार का भागीदारी सिद्धांत **(पाउलो फ्रेयर) और** बहुलता प्रतिमान **(जन सर्वेस)**
- प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल (TAM, **फ्रेड डेविस और रिचर्ड बैगोजी**)

2.0 साहित्य समीक्षा

"साहित्य समीक्षा एक विशेष विषय पर मौजूद विद्वानों के अध्ययन का आलोचनात्मक विश्लेषण है, जिसे आमतौर पर शैक्षिक अनुसंधान पत्रिकाओं और थीसिसों में पाया जाता है। यह नई अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान करता है, विशेषज्ञ अध्ययन, सिद्धांतों और विधियों को संक्षेपित और मूल्यांकन करके एक अच्छी तरह से आयोजित साहित्य समीक्षा विषय के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करती है, ज्ञान में रिक्तियों की पहचान करती है, और शोधकर्ता के काम के लिए मौजूद होती है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लेखों, किताबों और अन्य स्रोतों का व्यवस्थित खोज, चयन और संश्लेषण शामिल होता है। यह प्रक्रिया शोधकर्ता को पूर्व अनुसंधान पर निर्भरता बनाने में मदद करती है, उनके अध्ययन के महत्व को प्रमाणित करती है, और उनके क्षेत्र में ज्ञान के अग्रणी बनने में सहायक होती है"। (स्मिथ, 2010)

"Bhatiya and kiran. (2016), "इस शोध पत्र "रूलर डेवलपमेंट थ्रू ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया" में ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस द्वारा हो रही पहल की भूमिका का अध्ययन किया गया है इस शोध पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए हो रहे विभिन्न आई.सी.टी. सेवाओं में ग्रामीण विकास का नेतृत्व करने वाले विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक की पहचान करने का प्रयास किया गया है और साथ में भारत के विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं का अध्ययन करना । इस शोध पत्र में अध्ययन के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए द्वितीयक डेटा संग्रह विधि को प्रयोग में लिया गया है आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मिनिस्ट्री आफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आंकड़े, प्रकाशित शोध पत्र पुस्तक और समाचार पत्रों का सहयोग लिया गया है । इस शोध कार्य से पता चलता है की इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल विभिन्नता को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है । सरकार द्वारा भी विभिन्न पहलू से आई.सी.टी. के विकास में मदद की जा रही है जैसे की डिजिटल इंडिया अभियान, इस अभियान ने ई-गवर्नेंस को और अधिक शासक बनाया है साथ ही साथ ग्रामीण लोगों को अधिक तकनीकी जानकारी बनाने में मदद कर रहा है । ई-गवर्नेंस की सहायता से लोग एक बटन दबाने से भारत सरकार से संपर्क करने में सक्षम है जो लोगों को इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहा है । तकनीकी प्रगति की मदद से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल रहा है इसे ग्रामीण विकास का मार्ग सशक्त हो रहा है" ।

"Srivastava, N. (2015) "इस शोध कार्य में ई-गवर्नेंस के महत्व को परिचय प्रदान किया गया है इस शोध कार्य में द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग लिया गया है। विकसित देशों की तरह भारत में इसे कैसे अपनाया जा सकता है इस विषय पर

Sadhan सुभाष चन्द्र मल्ल

प्रकाश डाला गया है इसी के साथ इस ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है और इससे होने वाले फायदे पर भी प्रकाश डाला गया है। ई-गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसमें बताया गया है कि ई-गवर्नेंस ग्रामीण और नगरी क्षेत्र में सरकार के साथ नागरिकों के बीच जानकारी और संचार के त्रिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है इस सरकार के प्रशासन में सुधार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम भ्रष्टाचार के साथ सरकारी तंत्र में अधिक पारदर्शिता की दिशा में बदलाव देखा जा रहा है। इस अध्ययन में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को लागू करने में होने वाली चुनौतियों पर चर्चा किया गया है प्रमुख चुनौतियों के रूप में शिक्षा की कमी, तकनीकी निरक्षरता, जागरूकता में कमी, परिवर्तन की हिचकिचाहट जैसे कारकों को बताया गया है। इन सब के बावजूद शोधकर्ता ने यह पाया कि सरकार की कई ई-गवर्नेंस से संबंधित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक सफल है जैसे भूलेख, ई चैपाल, ई पोस्ट और ई पंचायत। साथ में साथ शोधकर्ता ने सुझाव दिया ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। आई.सी.टी. के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से डिजिटल आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए"।

"Chaudhari, k., Dalal,U., & Jha, R. (2011). इस शोध पत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आई.सी.टी. और वायरलेस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल शासन की भूमिका और प्रासंगिकता पर कार्य किया गया है। इस अध्ययन के लिए जल गांव जिले को शोध क्षेत्र के लिए चयनित किया गया है जल गांव जिले में वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक शासन की स्थिति की जांच किया गया है। जांच के अंतर्गत जल गांव जिले के ई-गवर्नेंस के लिए आई.सी.टी. वायरलेस प्रौद्योगिकियों का उपयोग से मॉडल के विकास पर केंद्रित है। इस अध्ययन के निष्कर्ष तौर पर पता चलता है कि वायरलेस तकनीक भारत में ग्रामीण प्रशासन के लिए ई-गवर्नेंस शुरू करने के लिए आवश्यक व्यापक इंटरनेट एक्सेस के लिए एक तेज, किफायती, सुविधाजनक समाधान के रूप में है। यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास और उसके प्रबंधन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभकारी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस शुरू करने के लिए वाई-फाई उपयुक्त विकल्प है"।

"Kavitha, K. S.(2020). इस अध्ययन कार्य में शोधकर्ता द्वारा केरल राज्य के अंतर्गत विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजना को अध्ययन क्षेत्र में लिया गया है। अध्ययन के लिए वर्णनात्मक और अनुभवजन्य शोध विधि को प्रयोग में लिया गया है अध्ययन के आंकड़ों के एकत्रित करने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं (5 विशेष ई-गवर्नेंस परियोजनाएं) को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है और उनसे प्रश्नावली विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। लोगों में उन परियोजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर सेवाओं के उपयोग और संतुष्टि के स्तर के साथ- साथ नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के द्वारा केरल राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आई.सी.टी. परियोजनाओं के प्रभाव का भी आकलन किया गया है। इस शोध कार्य में कुल 326 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिनमें से 160 उत्तरदाता महिलाएं थी और 166 पुरुष उत्तरदाता थे। इस अध्ययन से पता चलता है कि लोगों के बीच जागरूकता का मुख्य साधन उनके मित्र, रिश्तेदार को बता गया है, वही ग्रामीण क्षेत्र में समाचार पत्र और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी प्रभावी साधन के रूप में बताया गया है इसके बावजूद यह देखने को पाया गया की आधी जनसंख्या (43.9 प्रतिशत) में भी ई-गवर्नेंस के प्रति जागरूकता नहीं है। इस अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर लोग (88.1 प्रतिशत) ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रयोग की सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए लेते हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि ई-गवर्नेंस के उपयोगकर्ताओं में उम्र और जागरूकता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाई देता है। अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा कहा गया है कि शासन को ई-गवर्नेंस की जागरूकता को फैलाने के लिए उचित और प्रभावी कदमों को उठाना चाहिए। लोगों में ई-गवर्नेंस के प्रति संतुष्टि का भाव देखने को पाया गया है परंतु लोगों की भागीदारी की कमी भी देखने को मिली है। इसी के साथ-साथ लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी को भी एक अवरोध के रूप में बताया गया है। शोधकर्ता ने जागरूकता के स्तर , विभिन्न क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस की उपयोगिता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का सुझाव दिया है"।

"अग्रवाल और मेहरोत्रा (2017) में अपने शोध पत्र के अंतर्गत ई-गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा विशेष कर सरकारी सेवाएं प्रदान करने और अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आई.सी.टी. का उपयोग करना ई-गवर्नेंस सेवाएं कहलाती हैं। उनका यह अध्ययन ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ और बढ़ाओ के बारे में नागरिकों के परिपेक्ष और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले साइटों के उपयोग के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया

Sadh अभय शुक्ला

गया है । अध्ययन के अंतर्गत लोगों को तीन समूह में विभाजित कर दिया गया है अत्यधिक सुविधायुक्त, सकारात्मक विचारधारा वाले एवं तटस्थ विचारक के रूप में देखा गया है । अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं को उन इस गवर्नेंस सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी है जो उन्हें सीधे प्रभावित करती है जबकि जो इन सेवाओं के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रदर्शन से संबंधित होती है उन्हें उत्तरदाताओं में काम जागरूकता देखी गई है । अग्रवाल और मल्होत्रा के अनुसार सरकार को ई-गवर्नेंस के प्रति लोगों में जागरूकता स्तर को बढ़ाने की जरूरत है जिससे जनता बड़े पैमाने पर इन साइटों का उपयोग करेगी । उनके अनुसार गोपनीयता का मुद्दा एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में लोगों में ई-गवर्नेंस के प्रयोग के प्रति है सरकार को लोगों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गोपनीयता बरकरार रहेगा और उनके उत्तर का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा । ऐसा दिन में यह भी देखने को पाया गया कि समूह 2 में जो ई-गवर्नेंस सेवा साइटों को उपयोग करने के प्रति अधिक सकारात्मक उत्तरदाताओं के अनुसार की सेवाएं शासन के प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है वहीं समूह 1 के उत्तरदाता में ई - गवर्नेंस सुविधा का प्रयोग उच्च स्तर पर था क्योंकि इन लोगों के पास ही गवर्नेंस सेवा साइटों का उपयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाएं है । समूह एक और तीन की सेवाओं को अपने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में गोपनीयता के मुद्दे को माना , वही समूह दो के उत्तरदाताओं का मानना है कि ई सेवा ऑन के प्रयोग में कनेक्टिविटी टूल सबसे बड़ी बाधा है" ।

"**रॉबर्ट चैंबर्स (1979)** द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक "रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट" के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी और समुदाय के नेतृत्व के लिए विकसित की गई पहल के महत्व पर प्रकाश डाला है । चैंबर्स के अनुसार विकास के पारंपरिक के तरीके के द्वारा ग्रामीण विकास संभव नहीं है जिसके अंतर्गत टॉप-डाउन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना की गई है और बॉटम-अप दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की सिफारिश की जाती है । उनके अनुसार ग्रामीण प्रशासन से संबंधित निर्णय निर्णय लेने की प्रक्रिया में हाशिए पर रखे जाने वाले समूह को प्राथमिकता देने की आवश्यक है जिसमें विशेष कर महिलाएं और गरीबों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है । चैंबर्स ने सदैव अधिक भागीदारी और समावेशी दृष्टिकोण की वकालत किया है जिसके अंतर्गत शासन और प्रशासन ग्रामीण आबादी के साथ उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा । वह ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता को समझते हुए विकास की रणनीति में सदैव लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया हैं"।

"**हीक्स (2003)** इस पेपर में e-government-for-development परियोजनाओं की उच्च विफलता दर पर चर्चा की गई है, जिसे 'डिज़ाइन-रियलिटी गैप्स' योजना और वास्तविक कार्यान्वयन स्थितियों के बीच के अंतर के कारण बताया गया है। इसमें इन गैप्स की पहचान की गई है और विफलता के संभावित परिदृश्यों को समझाया गया है। जोखिमों को कम करने के लिए एक चरण-दर-चरण गाइड प्रदान की गई है जो विभिन्न लाभार्थियों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल करने की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। केस स्टडी यह दर्शाती है कि कैसे इस दृष्टिकोण का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया, जिसमें परियोजना ने उपयोगकर्ताओं की विविधता को शामिल किया और डिज़ाइन और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित किया। यह पेपर निष्कर्ष निकालता है कि यदि इसे अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाए, तो डिज़ाइन-रियलिटी गैप दृष्टिकोण ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की विफलता को काफी हद तक कम कर सकता है ।"

"**भटनागर (2004)** में अपनी पुस्तक "ई-गवर्नेंसरू फॉर्म विजन तो इंप्लीमेंटेशन - ए पार्क्टिकल गाइड विथ कैसे स्टडी" में इस बात पर जोर देते हैं कि शहरी ग्रामीण असमानता को समाप्त करने के लिए और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ई- गवर्नेंस की क्षमताओं का प्रयोग ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत करने पर जोर देना चाहिए। उनके अनुसार प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया को से व्यवस्थित कर सकती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सेवाओं का बेहतर वितरण किया जाना संभव हो सकेगा" ।

"**सिंह, ए. (2014).** इस शोध कार्य के अंतर्गत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शासन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर संबंध पर प्रकाश डाला गया है यह पेपर वर्तमान परिदृश्य में ई-गवर्नेंस के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौतियां और प्रयासों को संदर्भित करते हुए भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह शोध पत्र में बताया गया है कि आई.सी.टी. द्वारा ई-

Sadhna अभय शुक्ला

गवर्नेंस भारत में एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में उभरा है जिसका उद्देश्य नागरिक को तक सूचना और सेवाओं की पहुंच बढ़ाना एवं उनमें सुधार करना है। इस अध्ययन के अनुसार ई-गवर्नेंस में यूपी राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यहां की सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की ई-गवर्नेंस योजनाओं को अस्तित्व में लाया गया है जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। परंतु केंद्र सरकार और अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, शोधकर्ता का सुझाव है की राज्य भर में परियोजनाओं अनुप्रयोगों को लागू करने और उनका समर्थन करने के लिए यूपी सरकार को बड़े प्रयासों की आवश्यकता है"।

"वानी, एम., और तांत्रे, जेड.आई. (2018) अपने अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है की भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी तीव्र गति से बढ़ रही है इसके कारण के तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि भारत की 70 प्रतिषत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। शोध पत्र में प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आई.सी.टी. को प्रयोग में लेते हुए विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखा है । वर्ष 2020 तक भारत सरकार लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापक नागरिक सरकार संपर्क हासिल किया जा सके, इसके लिए सरकार पहले से ई-चैपाल, किसान कॉल सेंटर, आकाशगंगा, ज्ञान दूध और टाटा किसान केंद्र जैसी पहलो को प्रारंभ कर चुकी है। यह शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों के सहायता से ई-गवर्नेंस को बढ़ाने में आई.सी.टी. प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया है ।शोध के निष्कर्ष के रूप वर्णन किया गया कि भारत जैसे तहसील देश भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल विभाजन को खत्म करने में ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आई.सी.टी. ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया सहित चल रहे अन्य सरकारी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक नेटवर्क और भागीदारी के द्वारा ग्रामीण सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण समुदाय में पारदर्शिता के साथ बुनियादी सुविधाओं को किफायती दर में प्रदान करने के लिए एक गवर्नेंस का उपयोग आवश्यक माना गया है इसी के साथ ही ई-गवर्नेंस में आई.सी.टी. का सफल अनुप्रयोग ग्रामीण समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए व्यापक संविधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है"।

3. व्यापक क्षेत्र का वर्णन

यह शोध कार्य पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य में ई-गवर्नेंस के प्रभाव और संभावनाओं की गहन पड़ताल करता है। व्यापक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह अध्ययन विकास संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), ग्रामीण विकास, और गवर्नेंस के डिजिटल परिवर्तन को आपस में जोड़ता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और संभावनाएँ इसे विशेष अध्ययन का केंद्र बनाती हैं। यहाँ कृषि-प्रधान समाज, सीमित अवसंरचना, डिजिटल असमानता, और निरंतर बदलती शासन प्रणालियों ने ग्रामीण विकास को बहुआयामी बना दिया है। ऐसे में ई-गवर्नेंस, विशेषकर G2C (Government to Citizen) सेवाएँ, नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं की सीधी पहुँच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रही हैं।

ई-गवर्नेंस और ग्रामीण विकास का अंतर्संबंध: इस शोध के व्यापक क्षेत्र में ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक सशक्तिकरण, और सतत विकास। ई-गवर्नेंस यहाँ प्रशासनिक दक्षता, सेवा वितरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। मनरेगा, जनसुनवाई समाधान, डिजिटल इंडिया जैसी सेवाएँ ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से शासन को सुलभ, पारदर्शी और प्रभावकारी बनाया जा रहा है, जो ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का महत्व: शोध का व्यापक क्षेत्र ICT के नवाचारों और उनके सामाजिक प्रभाव को भी केंद्र में रखता है। ई-गवर्नेंस सेवाओं की सफलता ICT के उपयोग और उसके ग्राम्य समाज में प्रभावी

अभय शुक्ला

Sadhana

क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अध्ययन में सूचना प्रवाह, डिजिटल साक्षरता, और प्रौद्योगिकी स्वीकृति जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि ग्रामीण नागरिक कितनी सहजता से इन सेवाओं को अपना पा रहे हैं।

सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ: पूर्वांचल क्षेत्र में गहरी सांस्कृतिक जड़ें, भाषाई विविधता (भोजपुरी, अवधी आदि), और सामाजिक संरचनाएँ डिजिटल परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। इस शोध के व्यापक क्षेत्र में इन सामाजिक कारकों का विश्लेषण भी शामिल है कि कैसे ये कारक ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच, स्वीकृति और प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

शासन और नीति निर्माण के दृष्टिकोण: यह अध्ययन शासन प्रक्रिया और नीति निर्माण के परिप्रेक्ष्य में भी योगदान देता है। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार किस प्रकार नीति, रणनीतियाँ और प्रबंधन ढाँचे बनाकर डिजिटल सेवा वितरण को सुगम बना रही है। इसमें नीति निर्माताओं के लिए सिफारिशें विकसित करना और शासन के डिजिटलीकरण की व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करना भी शोध का महत्वपूर्ण भाग है।

विकास संचार का सिद्धांतात्मक आधार: यह शोध विकास संचार के प्रमुख सिद्धांतों – नवाचार के प्रसार का सिद्धांत, भागीदारी दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल आदि पर आधारित है। यह शोध पारंपरिक से लेकर डिजिटल माध्यमों तक के संचार तंत्र का विश्लेषण करता है कि वे ग्रामीण समुदायों में कैसे विकास और बदलाव की प्रेरणा देते हैं।

डिजिटल डिवाइड और चुनौतियाँ: शोध में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड, बुनियादी अवसंरचना की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और सांस्कृतिक अवरोधों को भी गहराई से समझा गया है। यह अध्ययन दिखाता है कि ये चुनौतियाँ किस प्रकार ई-गवर्नेंस के प्रभाव को सीमित करती हैं और इसके समाधान क्या हो सकते हैं।

इस शोध का व्यापक क्षेत्र पारंपरिक शासन मॉडल और डिजिटल युग के शासन के बीच पुल का निर्माण करता है। इसमें यह विश्लेषण किया जाता है कि कैसे डिज़िटल प्लेटफॉर्म्स ग्रामीण विकास में नई संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं और सरकारी सेवाओं को ग्रामीण नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचा रहे हैं। ई-गवर्नेंस, न केवल तकनीकी पहलू तक सीमित है बल्कि यह ग्रामीण भारत में शासन, प्रशासन, नागरिक सहभागिता और सामाजिक न्याय के नए प्रतिमान स्थापित करने का सशक्त उपकरण बन रहा है। शोध का उद्देश्य नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से इन सेवाओं की प्रभावशीलता को बेहतर बनाना और ग्रामीण विकास के लिए एक ठोस डिजिटल आधार तैयार करना है।

4. अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं के मौजूदा बुनियादी ढांचे का अध्ययन।
2. ग्रामीण आबादी का ई-गवर्नेंस(जी2सी) सेवाओं की पहुंच और उपयोग का अध्ययन।
3. ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेंस सेवाओं को स्वीकृति देने वाले प्रमुख कारकों (दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और इत्यादि) का अध्ययन।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस (जी2सी) सेवाओं को प्रभावी ढंग से अपनाने में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण।
5. ग्रामीण शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी में ई- गवर्नेंस (जी2सी) सेवाओं की भूमिका का अध्ययन।
6. ग्रामीण संदर्भों में ई-गवर्नेंस की जी2सी सेवाओं की पहुंच को बेहतर करने लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक उपयोगी रणनीति विकसित करना।

5 अनुसंधान अभिकल्प

इस अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए डिजिटल संचार के तौर पर ई-गवर्नेंस के प्रमुख परियोजना की भूमिका और उपयोगिता का अध्ययन किया गया है। इस शोध कार्य के अंतर्गत ई-गवर्नेंस सेवाओं पर अध्ययन किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं -

अभय शुक्ला

Sadhu

Schemes / Services

1. MGNREGA / Janmanrega
2. UIDAI
3. E-Banking
4. Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin / AwaasApp
5. Gram Samvaad
6. Meri Sadak
7. SAMBAL
8. Kaushal Panjee - Skill Register
9. DIGILOCKER
10. E-District (eSathi UP)
11. Jansunwai Samadhan
12. Bhulekh
13. Aapurti
14. SSPY-UP
15. Jansunwai
16. Digital India
17. Ayuṣhman Bharat Digital Mission (ABDM)

5.1 अनुसंधान विधि - वर्णनात्मक शोध विधि और अन्वेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

5.2 अनुसंधान की प्रकृति - इस अध्ययन कार्य में मिश्रित प्रकृति का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

5.3 अध्ययन में प्रयुक्त चर –

- स्वतंत्र चर- सूचना एवं संचार तकनीकी, ई-गवर्नेंस सेवाएं
- आश्रित चर- ग्रामीण विकास
- अन्य चर - डिजिटल विभाजन, आई.सी.टी. और ई-गवर्नेंस के प्रयोग में आने वाली चुनौतियां, प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारक

5.4 न्यादर्श तकनीकी

इस अध्ययन को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, अर्थात इस अध्ययन की जनसंख्या उन 19 जिलों में से चयनित जिलों की ग्रामीण जनसंख्या है।

1.	आजमगढ़
2.	कुशीनगर
3.	गाजीपुर
4.	गोरखपुर
5.	चन्दौली
6.	जौनपुर
7.	देवरिया
8.	प्रयागराज
9.	बलिया
10.	बस्ती

11.	भदोही
12.	मऊ
13.	महाराजगंज
14.	मिर्ज़ापुर
15.	रायबरेली
16.	वाराणसी
17.	संत कबीर नगर
18.	सिद्धार्थनगर
19.	सोनभद्र

इस शोध के अंतर्गत **बहुचरणी प्रतिचयन तकनीक** को प्रयोग में लिया जाएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्वांचल के 19 जिलों में से आने वाले तीन महानगरों का चयन किया जाएगा जो की प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जिले है।

1. प्रयागराज
2. वाराणसी
3. गोरखपुर

महानगरों में अन्य नगरों के अनुसार अधिक जनसंख्या रहती है और बुनियादी सुविधाओं की संरचना भी बेहतर होती है इसी कारण इस अध्ययन में पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले तीनों महानगरी जिलों के समीप ग्रामीण क्षेत्र को अध्ययन में सम्मिलित किया जाए। दूसरे चरण में चयनित जिलों की जनसंख्या को केंद्र में रखते हुए कोचरन या यामाने सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि. नमूना चयन किया जाएगा, जिसमे 50 प्रतिशत पुरुष और 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

जिला	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या
प्रयागराज	6000000	4481518
वाराणसी	3676841	2079790
गोरखपुर	4440895	3604766
कुल योग	14117736	10166074

- Krejcic and Morgan table formula = x^2.NP (1-P)/ d^2 (n-1)+x^2P(1-P)

X= Level of confident interval on 99 percent level of confident (2.576)

P= population portion (50%)

d= degree of accuracy 0.05

n= number of estimated population

n = 2.576*10166074*50 (1-50)/ .05^2 (10166074-1)+2.576*50(1-50) = 666

कुल न्यादर्श संख्या – 666

साक्षात्कार विधि के अंतर्गत प्रतीक ब्लॉक से दो या तीन ऐसे अधिकारियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जो ई-गवर्नेंस सेवाओं को प्रतिपादित करते हैं साथ ही साथ प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी का भी साक्षात्कार किया जाएगा।

प्रतिदर्श की आयु - 18 से 56+ वर्ष

अभय शुक्ला

5.5 शोध तकनीक -

Sadhna

आंकड़ों के एकत्रित करने के उपकरण

शोध कार्य के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीय के दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा प्राथमिक आंकड़ों के लिए सर्वेक्षण (अनुसूची उपकरण), साक्षात्कार एवं अवलोकन विधि का सहयोग लिया जाएगा वही द्वितीयक आंकड़ों के लिए विभिन्न शोध पत्रों व ई- गवर्नेंस सेवाओं में सफल देशों के अध्ययनों को शामिल किया जाएगा।

अनुसूची उपकरण के निर्माण के लिए पूर्व के अध्ययन में प्रयोग की गई अनुसूची के सहयोग के साथ शोध उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार अनुसूची के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा।

आंकड़ों का स्रोत

इस शोध कार्य के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीय के दोनों प्रकार के आंकड़ों को उपयोग में लाया जाएगा।

प्राथमिक आंकड़े - इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली तकनीक, साक्षात्कार विधि और अवलोकन विधि को प्रयोग में लिया जाएगा।

द्वितीयक आंकड़े - इन आंकड़ों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, शोध पत्र, समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों एवं ई- गवर्नेंस सेवाओं में सफल देशों के अध्ययनों का सहयोग लिया जाएगा।

6 अपेक्षित निष्कर्ष

पूर्वांचल क्षेत्र में ई-गवर्नेंस (जी2सी) सेवाओं के कार्यान्वयन से ग्रामीण नागरिकों को सरकार की सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी। अध्ययन से यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे मनरेगा, जनधन योजना, आधार सेवाओं, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे। इससे न केवल सेवाओं की पहुँच में वृद्धि होगी, बल्कि सेवा वितरण में समय की बचत और प्रक्रिया की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। यह परिवर्तन ग्रामीण शासन को अधिक दक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाएगा। इसके अतिरिक्त, इस शोध के माध्यम से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। विशेषकर महिलाएं, युवा और पिछड़े वर्ग के लोग डिजिटल साधनों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकेंगे। शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होने से नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे शासन में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि वे नीतियों में सुधार कर सकें और ई-गवर्नेंस की योजनाओं को जमीनी स्तर तक बेहतर ढंग से पहुँचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचे और आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र में सतत विकास को गति मिलेगी।

हालांकि ई-गवर्नेंस सेवाओं के अनेक सकारात्मक पहलू हैं, फिर भी इस अध्ययन में कुछ नकारात्मक पक्ष और चुनौतियाँ भी सामने आने की संभावना है। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल डिवाइड की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के निम्न स्तर, सामाजिक-आर्थिक विषमता और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच के कारण उत्पन्न होती है। इस वजह से ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ समाज के केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित रह सकता है और वंचित वर्ग अब भी पीछे छूट सकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो ई-गवर्नेंस की सफलता बुनियादी ढांचे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति और हार्डवेयर सुविधा पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इन संसाधनों की कमी देखी जाती है, जिससे ई-सेवाओं का सुचारू संचालन बाधित हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी भय ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का उपयोग करने से रोक सकता है। ऐसे में ई-गवर्नेंस की उपयोगिता सीमित रह सकती है और इसका उद्देश्य अधूरा रह सकता है। एक और महत्वपूर्ण चिंता गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर है। ई-गवर्नेंस सेवाओं में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जाती है, जिससे डाटा चोरी, हैकिंग और दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। यदि सरकार द्वारा पर्याप्त साइबर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो नागरिकों में इन सेवाओं के प्रति अविश्वास

अक्षय शुक्ला

Sadhe

उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक अक्षमता भी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण में कमी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन में असमर्थता भी ई-गवर्नेंस के प्रभाव को सीमित कर सकती है। इसके अलावा, पूर्वांचल के कुछ दूरस्थ इलाकों में इन सेवाओं का असमान वितरण देखने को मिल सकता है जिससे वहाँ के नागरिक पिछड़ सकते हैं।

कुल मिलाकर, इस शोध से यह अपेक्षा की जाती है कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन व्यवस्था में बदलाव आएगा और नागरिक सेवाओं की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही यह भी संभव है कि ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न बाधाएँ और सीमाएं भी सामने आएंगी, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन के दौरान ध्यान देने योग्य होंगी। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शासन की दिशा में आगे बढ़ते भारत के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में काम करेगा और भविष्य में ई-गवर्नेंस की रणनीतियों को मजबूती प्रदान करने के लिए ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

ग्रन्थसूची

1. United Nations. (2020). UN E-Government Survey 2020. Retrieved from [https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020]

2. Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The Public Opinion Quarterly, 37(4), 509-523.

3. Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality? Public Administration Review, 62(4), 424-433.

4. Heeks, R. (2003). Most E-Government-for-Development Projects Fail: How Can Risks Be Reduced? iGovernment Working Paper Series, 1(3).

5. Norris, D. F., & Moon, M. J. (2005). Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare? Public Administration Review, 65(1), 64-75.

6. Choguill, C.L. (1996). Rural Development: Putting the Last First. Longman.

7. Shrestha, R.B. (2006). Rural Development in Nepal: An Approach. Tribhuvan University Journal, 25(1), 97-108.

Sadhna

अभय शुक्ला

8. Kavithā, K. S. (2020). Electronic Governance and Development: An Evaluative Study of Government Initiatives in Kerala. Shodhganga doctoral dissertation, University of Kerala.Department: Department of Commerce. http://hdl.handle.net/10603/445373

9. Chaudhari, K., Dalal, U., & Jha, R. (2011). E-Governance in Rural India: Need of Broadband Connectivity Using Wireless Technology. Wireless Engineering and Technology, 2(3), 9. DOI: 10.4236/wet.2011.23029.

10. Srivastava, N. (2015). E-Governance in Rural India. *International Journal of Computer Science and Information Technologies, 6*(1), 741-744.

11. Bhatia, A., & Kiran, C. (2016). Rural Development through E-Governance Initiatives in India. IOSR Jöurnal of Business and Management (IOSR-JBM),(18) 61-69. e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319–7668.

12. World Bank. (n.d.). E-Government and the Digital Divide. Retrieved from [https://www.worldbank.org/en/topic/egovernment]

13. Bhatnagar, S. (2004). E-government: From vision to implementation – A practical guide with case studies (pp. 120-135). Commonwealth Secretariat.

14. Toyama, K. (2011). Technology as amplifier in international development. Association for Computing Machinery. New York, NY, United States.

15. Singh, A. (2014). E-governance Initiatives in Uttar Pradesh. Asian Journal of Technology & Management Research, 4(1), ISSN: 2249-0892.

16. Singh, S. K., & Medhavi, S. (2021). E-Governance in Uttar Pradesh: Concept, Initiatives and Challenges. International Journal for Research in Applied Science & Engineering

अक्षय शुक्ला

Sadhana

Technology, 9(3), ISSN: 2321-9653.

17. Chambers, R. (1979). Rural Development: Putting the Last First. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

18. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.

19. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

20. Chun, S. A., Shulman, S., & Sandoval, R. (2005). Reconsidering the digital divide: Lessons from an e-government benchmarking study. Public Administration Review, 65(5), 565-575.

21. Gupta, M. P., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of VKBZ-LH-VH- in a government organization in a developing country: An empirical study. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 35(1), 1-16.

22. Bannister, F., & Connolly, R. (2011). The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government. Policy & Internet, 3(1).

23. UNDP. (2004). E-Governance for Development: A Focus on Rural India. United Nations Development Programme.

Web sites

Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare? on JSTOR
http://hdl.handle.net/10603/445373
Key e-Governance Project | Official website of State Portal, Government of Uttar Pradesh, India (up.gov.in)
http://surl.li/aqxeng
https://varanasi.nic.in/demography/
https://gorakhpur.nic.in/at-a-glance/
https://gorakhpur.nic.in/demography/
https://upnrhm.gov.in/assets/site-files/dhap/districts/Allahabad/Allahabad_4_.pdf

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language Hindi

Submission Information

Author Name	abhay_phd
Title	synopsis
Paper/Submission ID	2238806
Submitted by	drsadhana@uprtou.ac.in
Submission Date	2024-08-17 14:20:10
Document type	Synopsis

Result Information

Similarity **0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

Sadhana

अभय शुक्ला

DrillBit

DrillBit Similarity Report

0	3	A	A-Satisfactory (0-10%) B-Upgrade (11-40%) C-Poor (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)
SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE	

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	Paper Submitted to Awadesh Pratap Singh University, Rewa	<1	Student Paper
2	Thesis Submitted to Shodhganga, shodhganga.inflibnet.ac.in	<1	Publication
3	Thesis Submitted to Shodhganga, shodhganga.inflibnet.ac.in	<1	Publication

Sadhna   अभय शुक्ला